डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 06 ● भोपाल ● 16-31 अगस्त, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

तेंदूपत्ता संग्राहकों के हितों का रखा जायेगा पूरा-पूरा ख्याल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सतना के बरौंधा में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये प्रारंभ की चरण पादुका योजना

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार वनवासियों के हितों का पूरा-पूरा ख्याल रखेगी। राज्य सरकार ने उनके हितों में अनेक निर्णय लिये हैं। वनवासियों को वनोपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिये राज्य सरकार महुआ और अचार की गुठली जैसी वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2015-16में बोनस का लगभग 71 करोड़ रुपये वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान सतना जिले के मझगवां विकासखण्ड के बरौंधा में तेंदूपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संग्राहकों को अपने हाथों से जूते-चप्पल पहनाकर और पानी की बॉटल देकर चरण पादुका योजना की शुरूआत की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महुआ फूल की खरीदी भी 30 रुपये प्रति किलो की दर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मझगवां के वन क्षेत्र में अचार, महुआ और करंज जैसी कई तरह की वनोपज पैदा होती है। इनकी खरीदी के लिये वन विभाग बरौंधा, कौहारी, पछीत और पाथरकछार में 4 खरीदी केन्द्र खोलेगा।

गरीबों की आवास समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पक्का मकान देने की योजना में सतना जिले में 23 हजार और वन ग्रामों में 6000 मकान स्वीकृत किये गये हैं। वन क्षेत्र में इस वर्ष 5000 पक्के मकानों का विशेष पैकेज दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के संकल्प के तहत पाथरकछार में 30 करोड़ 64 लाख रुपये के तालाब और अन्य ग्रामों में सिंचाई तालाब बनाकर पानी की व्यवस्था की जायेगी। क्षेत्र में 5000 कपिलधारा के कुएँ भी बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस वनवासी क्षेत्र में 50 कस्टम हायरिंग केन्द्र खोले जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था की जायेगी। पहाड़ी अंचल के इन गाँव में दीनदयाल चलित अस्पताल की व्यवस्था भी की जायेगी। उन्होंने क्षेत्र के हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी के रूप में उन्नयन करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने वनोपज और बाँस शिल्प की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

आयुक्त, सहकारिता द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल। श्री आशुतोष अवस्थी, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश ने राज्य सहकारी संघ में गतिविधियों की समीक्षा की तथा प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के आवश्यक निर्देश दिये। प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने संघ की गतिविधियों की जानकारी दी।

भंडार क्षमता में वृद्धि के लिये 5 लाख मीट्रिक टन के शीत गृह बनेंगे

भोपाल। राज्य शासन द्वारा कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से फल-सब्जी, मसाला, पुष्प तथा औषधीय फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने के लिए अनुदान सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन विभाग द्वारा सतत प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में उद्यानिकी का रकबा 17.12 लाख हेक्टेयर हो गया है।

उत्पादित उद्यानिकी एवं कृषि फसलों पर आधारित खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता संबंधी नवीन प्रावधान उद्योग संवर्धन नीति-2014 में जोड़े गये हैं। इससे प्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ेगी एवं उद्यानिकी उत्पाद निरंतर बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे।

निजी क्षेत्र में आगामी दो वर्षों में पाँच लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के शीत गृह निर्मित कराये जाने के लिए नश्वर उत्पादों की भण्डरण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना से अभी तक 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्षमता के शीत गृह निर्मित किए जायेंगे। शीत गृहों के निर्माण से फसलोत्तर नुकसान की कमी होगी और अधिक उत्पादन की स्थिति में मूल्यो में गिरावट को भी आंशिक रूप से रोका जा सकेगा।

प्रदेश में प्याज भण्डारण की वर्तमान क्षमता को दो वर्षों में बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 70 हजार मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भण्डार गृहों का निर्माण किया जाकर 14 करोड़ 92 लाख की अनुदान राशि कृषकों को दी गई है। खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 155 प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त हुए है।

सरदार सरोवर डूब क्षेत्र के प्रभावितों के लिये श्री चौहान ने की अनेक सौगातों की घोषणा

पुनर्वास स्थल पर दिये गये अधिकार-पत्रों की रजिस्ट्री करवायेगी सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ सरदार सरोवर डूब क्षेत्र के प्रभावितों के साथ रू-ब-रू चर्चा करने के बाद उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अनेक सौगातों की घोषणा की। प्रभावितों का आव्हान किया कि पुनर्वास कार्य सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाये कि यह कार्य राजी-खुशी सम्पन्न हो। सरकार आत्मीय भाव से बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है। आगे जो भी समस्या सामने आयेगी, उसका पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जायेगा। उन्होंने प्रभावित परिवारों का आव्हान किया कि वे सरदार सरोवर परियोजना और पुनर्वास के प्रयासों को लेकर किये जा रहे विपक्ष के भ्रामक दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं दें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निसरपुर कस्बे को आदर्श शहर बनाया जायेगा। पानी भरने के बाद जो क्षेत्र टापू बनेंगे वहाँ, पुल, सड़कें और पहुँच मार्ग बनाए जायेंगे। जिन क्षेत्रों में खेती संभव नहीं होगी, उसका किसानों की माँग पर मुआवजा दिया जायेगा। डूब क्षेत्र के लोगों को जो विशेष पैकेज मिला है, विस्थापन के अधिग्रहीत भूमि स्वामियों को भी मिलेगा। ऐसे परिवार जिनकी 25 प्रतिशत से कम भूमि डूब में आयी है, उनको भी पैकेज का लाभ दिया जायेगा। पैकेज की गणना डूब में गई भूमि के अनुपात से की जायेगी। पुनर्वास स्थल पर दिये गये हर अधिकार-पत्र की रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सिंचाई के लिए किसानों द्वारा डलवाई गई पाइप लाइन का भी सर्वेक्षण करवाकर मुआवजा दिया जायेगा। मकान बनवाने के लिए 5 लाख रुपये का विशेष पैकेज दिया जायेगा। यह राशि आकस्मिक व्यय के लिये दी गई राशि 80 हजार रूपये के अतिरिक्त होगी।

श्री चौहान ने कहा कि सरकार पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के लिये पूरी ताकत के साथ कार्य करेगी। पुनर्वास कार्य बेहतर से बेहतर होंगे। पुनर्वास स्थल के सारे गाँव आदर्श गाँव के रूप में विकसित किये जायेंगे। पैसा किसी भी हाल में आड़े नहीं आयेगा। कार्य पूर्णता की समय-सीमा तो है किन्तु कार्य रूकने नहीं दिया जायेगा, निरंतर जारी रहेगा। आगे जो भी समस्या आएगी, उसका तत्परता और संवेदनशीलता से समाधान होता जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास के लिए पहले भी 600 करोड़ का पैकेज दिया गया था जिसमें 5 लाख 62 हजार रूपये मिलने थे। अब उस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रूपये किया गया है। सरकारी, धर्मस्व एवं समाज के मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 27 करोड़ रूपये की पूरी राशि दी जायेगी। आवश्यकता होने पर और राशि भी दी जायेगी। सभी समाजों के मांगलिक भवनों के लिए उपलब्धता के आधार पर भूखण्ड दिये जायेंगे। सर्वे में छूट गये जायज परिवारों के लिए फिर से सर्वे करवाया जायेगा। पात्र परिवारों को भी सभी प्रकार की राहत सुविधाएँ मिलेगी। गाँधी जी के अस्थि-कलश को भव्य स्मारक में स्थापित किया जायेगा। पात्रता निर्धारण संबंधी विसंगतियों में जो नाम प्रकाश में आयेंगे, उनका पुनः सर्वे कराकर निराकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गाँव आज जिस स्थिति में है, पुनर्वास स्थल के गाँव उससे कई गुना बेहतर स्थिति में होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 अप्रैल 1961 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू ने परियोजना का शिलान्यास किया था। उसके बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। उन्होंने इसमें परिवर्तन के लिये कोई प्रयास नहीं किये। यद्यपि जब संविद सरकार बनी, तब जरूर तत्कालीन जनसंघ के मंत्रियों ने इसकी ऊँचाई का विरोध किया था। कुछ समय के लिये परियोजना लंबित भी हुई थी। किन्तु वर्ष 1985 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी से प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ट्रिब्यूनल को सौंपने और उसके निर्णयों के क्रियान्वयन की व्यवस्था करवा दी थी। मुख्यमंत्री ने भ्रामक दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देने का आव्हान करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि पानी भरने की अनिवार्यता की स्थिति में भी डूब क्षेत्र के लोग सुविधा से रहें। इसी मंशा से पुनर्वास प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास में दतिया प्रदेश में अव्वल

भोपाल। जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्र ने आवास क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए। दतिया जिला प्रधानमंत्री आवास योजना में औसत के आधार पर प्रदेश में अव्वल स्थिति और देश में पांचवें स्थान पर है। मंत्री डॉ.मिश्र ने जिला पंचायत दतिया के सभाकक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों एवं जिले के अधिकारियों के समक्ष हितग्राहियों को प्रोत्साहित कर उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मेरा संकल्प है कि दतिया जिला विभिन्न योजनाओं में देश में अव्वल बने, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान पर आने के लिए सभी अधिकारी संकल्पित हों। संकल्प मजबूत रहेगा तो प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त होगा।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इनमें नर्मदा सोनी को श्रवण यंत्र, आठ व्यक्तियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दो हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत तीन, स्नेह सरोकार के अंतर्गत दो हितग्राहियों, उज्जवला योजना के अंतर्गत पाँच गैस कनेक्शन, अनसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत तीन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहक चुन्नी और बुधिया को पहनाई चप्पल

भोपाल। सतना जिले के वन ग्राम जवारिन की तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती चुन्नी खैरवार पति ददुआ खैरवार और ग्राम छरी की श्रीमती बुधिया मवासी पति श्री शिवमारन मवासी को अब पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। न ही, जंगल में साफ और ठण्डा पानी पीने के लिये भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार 31 जुलाई 2017 को ग्राम बरौंधा पहुँचकर इन्हें अपने हाथों से चप्पल पहनाई और सेलो की पानी की बोतल दी। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चप्पल पहनाई एवं सेलो की पानी की बॉटल दी।

उपस्थित जन समुदाय उस समय भाव-विभोर हो गया जब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इनके पैरों मे चप्पल पहनाई। तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती चुन्नी खैरवार और श्रीमती बुधिया मवासी मुख्यमंत्री की आत्मीयता से काफी प्रभावित हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती चुन्नी खैरवार लघु वनोपज समिति, कौहारी और श्रीमती बुधिया मवासी पाथरकछार लघु वनोपज समिति के क्षेत्र के वन ग्रामों में जीवन-यापन करती हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये प्रदेश में चरणपादुका योजना का शुभारंभ सोमवार 31 जुलाई को ग्राम बरौधा जिला सतना से किया। मुख्यमंत्री ने 18अप्रैल 2017 को उमरिया में घोषणा की थी कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये चरणपादुका योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला को चप्पल और एक पुरुष को जूता पहनाया जाएगा तथा पानी की बोतल

निःशुल्क दी जाएगी। योजना से 21.50 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहक लाभान्वित होंगे।

श्री के.सी. गुप्ता प्रमुख सचिव सहकारिता

भोपाल। राज्य शासन द्वारा भाप्रसे के 9 अधिकारियों की नवीन पद स्थापना आदेश जारी किये गये हैं। श्री के.सी. गुप्ता को प्रमुख सचिव सहकारिता तथा श्री अजीत केसरी को प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

क्र	नाम	वर्तमान पद-स्थापना	नवीन पद-स्थापना
1.	श्री प्रभांशु कमल	अपर मुज़्य सचिव, अनुसूचित जति कल्याण तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) अतिरिक्त प्रभार	अपर मुज़्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ)
2.	श्री बी.आर. नायडू	अपर मुज़्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग	अपर मुज़्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
3.	श्री आशीष उपाध्याय	प्रमुज़ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग	प्रमुज़ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
4.	श्री एस.एन. मिश्रा	प्रमुज़ सचिव, परिवहन विभाग तथा मुज़्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी	प्रमुज़ सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं परिवहन विभाग तथा मुज़्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी
5.	श्री अश्विनी कुमार राय	प्रमुज़ सचिव, पशुपालन विभाग	प्रमुज़ सचिव, श्रम विभाग
6.	श्री अजीत केसरी	प्रमुज़ सचिव, सहकारिता विभाग	प्रमुज़ सचिव, पशुपालन विभाग
7.	श्री अशोक शाह	प्रमुज़ सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुज़ सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) एवं संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान
8.	श्री के.सी. गुप्ता	प्रमुज़ सचिव, ज़ाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	प्रमुज़ सचिव, सहकारिता विभाग
9.	श्रीमती नीलम शमी राव	प्रमुज़ सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुज़ सचिव, ज़ाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कृषि विभाग की हितग्राही-मूलक योजना आधार नम्बर से जुड़ेंगी

कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश

भोपाल। प्रदेश में केन्द्र सरकार की मदद से संचालित आदिवासी उप योजना में हितग्राही-मूलक योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी) में आधार नम्बर से जोड़ने के निर्देश किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जिला कलेक्टर्स को दिये हैं।

राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को योजना में लाभान्वित हितग्राहियों के खेतों पर रेण्डम आधार पर फसल कटाई प्रयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। योजनाओं को पारदर्शी और परिणाम-मूलक बनाने के मकसद से प्रभारी अधिकारी जिलों में कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या के दो प्रतिशत अथवा 100 फसल कटाई प्रयोग, जो भी कम हो, उस आधार पर प्रयोग करेंगे। आदिवासी उप योजना में अनुसूचित-जनजाति के किसानों को मुख्य रूप से उन्नत किस्म की हरी खाद का बीज, जैविक खाद, जैव-उर्वरक और जैविक कीटनाशक अनुदान पर उपलब्ध करवायी जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ-बीमांकन की तिथि बढ़ी

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश जारी

भोपाल। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिसूचित क्षेत्रों में फसलों के लिये कृषकों के ऋण खातों से तय समय-सीमा में प्रीमियम काटने के निर्देश हैं। बैंक शाखाओं में कनेक्टिविटी अथवा सर्वर स्पीड की समस्या होने पर किसानों को बीमांकन का विवरण ऑफ लाइन यूटिलिटी के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज किये जाने की सुविधा दी गयी है।

प्रदेश में खरीफ-2017 के लिये बैंकों द्वारा प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि 16अगस्त निर्धारित है। इसके साथ ही फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों का विवरण दर्ज करने और कृषक अंश प्रीमियम पूर्ण विवरण के साथ बीमा कम्पनियों में जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गयी है। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव श्री प्रेमचंद मीना ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि इन तिथियों में ऑनलाइन सुविधा न होने पर जानकारी ऑफलाइन दर्ज की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर बीमांकन की जानकारी अपलोड नहीं होने पर किसानों को बीमा योजना से वंचित नहीं किया जा सकता है।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कलेक्टर्स से कहा है कि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन यूटिलिटी पर भी पोर्टल दर्ज नहीं हो पाने पर विशेष परिस्थितियों में पूर्व वर्ष की भाँति बीमांकन, प्रीमियम कटौत्रा की कार्यवाही कर पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

प्रवेश प्रारंभ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

जनता की सहभागिता से ही पर्यावरण संरक्षण - मुख्यमंत्री

पर्यावरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में जनता को जोड़ कर किए गए प्रयास ही सफल है। समाज यदि तय कर ले तो वह एक दिन में 7 करोड़ 14 लाख पौधे लगा सकता है। नदी संरक्षण की अभूतपूर्व पहल कर सकता है। इन अभूतपूर्व सफलताओं का आधार समाज को आगे कर सरकार द्वारा किये गये प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2017 का दो दिवसीय आयोजन यहाँ किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के कार्य अकेले सरकार नहीं कर सकती। समाज का साथ में खड़ा होना जरूरी है। प्रदेश में 2 जुलाई को हुआ वृक्षारोपण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नर्मदा नदी, वृक्षारोपण के प्रति ऐसा उत्सवी माहौल था कि पौध-रोपण करना गर्व का विषय बन गया था। पौध-रोपण में शामिल नहीं होना लोक लज्जा का कारण माना जाने लगा था। उन्होंने कहा कि पौध-रोपण कार्य निरंतर अलग-अलग स्थलों पर हर वर्ष चलेगा। प्रदेश नर्मदा नदी के संरक्षण के अभियान से नदियाँ बचाने का रा%य बना है। अगले वर्ष से ताप्ती, बेतवा और क्षिप्रा जैसी अन्य नदियों के संरक्षण के कार्य जन-सहभागिता से किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा प्रदेश की जीवन-रेखा है। विद्युत, सिंचाई और पेयजल का स्त्रोत है। नर्मदा का प्रवाह कम नहीं होने दिया जायेगा। वृक्षारोपण के साथ ही नदी में जल-मल को रोकने के लिये नर्मदा किनारे के सभी 18शहरों में सीवरेज प्लान्ट लगाने, पूजन सामग्री कुंडों में प्रवाहित करने, अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम और कचरे से ऊर्जा बनाने के प्रयास किये गये हैं। नर्मदा के दोनों तटों पर मदिरा का विक्रय बंद करवाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की मूल चेतना जड़, चेतन सभी को एक समान मानने और विश्व के कल्याण की है। इसीलिये पशुओं को देवी-देवताओं के साथ जोड़ कर आराधना की जाती है। गोर्वधन पूजा भी प्रकृति की उपासना ही है। यही चेतना सरकार का संकल्प है। ऐसा कोई उद्योग जो मानव, पशु-पक्षी जीवन के लिए खतरनाक है, प्रदेश की धरती पर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह ऐसी धरती छोड़े, जो मानव और अन्य प्रजातियों को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नया वातावरण बनाया है। उन्होंने धरती को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने की सोच के साथ कार्य किया है। इसके प्रभावी परिणाम दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना की। धरती को प्राणी मात्र के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रिब्यूनल को कठोर दृष्टिकोण रखने की जरूरत बताई। उन्होंने आव्हान किया कि वनों, प्रकृति का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। वन्य-प्राणियों के घर सुरक्षित रहे, साथ ही इंसान के घर भी नहीं टूटे इस दिशा में चिंतन किया जाये। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी का चिंतन पर्यावरण सरंक्षण के प्रयासों को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि संगोष्ठी के निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के प्रयासों में सरकार का पूरा सहयोग रहेगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति सोच में परिवर्तन समय की जरूरत है। दृष्टिकोण कैसा हो, इस विषय पर चिंतन होना चाहिए। साल के वृक्ष का उदाहरण देते हुए बताया कि 20 वर्ष के चक्र में लगने वाला कीड़ा 18लाख साल के पेड़ खत्म कर देता हैं। ऐसी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति विकास और शोध की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वनवासियों का वन के प्रति आसक्ति का आधार आजीविका है। वन संरक्षण के लिये वन के साथ उनके जुड़ाव को बढ़ाने के प्रयास जरूरी है। लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिश्यू कल्चर द्वारा पौध-रोपण से वनीकरण के प्रयासों पर विचार किया जाना चाहिये। वन हल्दी, मूसली आदि अनेक औषधीयाँ विलुप्त हो रही हैं। उनको लैब में तैयार कर वनवासियों को देने के प्रयासों पर विचार हो। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने को भारतीय संस्कृति में यज्ञ कराने के समान पुण्य का कार्य माना गया है। नदी साफ करना, जल और प्रदूषण रोकना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस लिए यह विचार किया जाना चाहिए कि जहाँ वन सुरक्षित है, वहाँ के रहवासी के लिए वन उनके विकास का माध्यम बने। वन संरक्षण के लिये उनको बर्बाद नहीं किया जाये। परियोजनाओं के प्रति पर्यावरणीय चिंतन भी समग्र दृष्टि से किया जाये। विद्युत उत्पादन की जल आधारित परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ एकड़ में वृक्षों की रक्षा के लिए परियोजना 30 से 35 वर्षों से लंबित है। परियोजना यदि समय पर शुरू हो जाती तो कोयले से विद्युत उत्पादन से होने वाले प्रदूषण की भारी मात्रा में बचत हो जाती। उन्होंने इस दिशा में चिंतन का अनुरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा पौध-रोपण की पहल की सराहना करते हुए कहा कि निर्णय लेने और क्रियान्वयन की विशिष्ट क्षमता उनमें है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की क्रियात्मक पहल 5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिलवा कर की है। इस एक कार्य से 20 हजार करोड़ वृक्षों की रक्षा हुई है। इस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास जरूरी है। उन्होंने एन.जी.टी. के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाये गये कदमों की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में पर्यावरणीय चेतना बनी है। संगोष्ठी के चिंतन को राज्य में लागू करने का आश्वासन दिया।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमेन न्यायाधिपति श्री स्वतंत्र कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आग्रही बन कर प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि केवल सस्टेनेबल डेव्लेपमेंट के लिए पेड़ काटे जाने चाहिये वह भी तब जब एक पेड़ के बदले में 10 पेड़ लगाये जाये। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ सम्मानीय व्यवहार जरूरी है। यदि प्रकृति का अपमान किया गया तो उसके परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। विगत दिनों की प्राकृतिक विभीषिकाएँ, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रकृति से जिसकी भरपाई हो सके, उससे अधिक नहीं लिया जाना चाहिये। उन्होंने आव्हान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये सारे विश्व को परिवार मानकर हर घर, गली, मोहल्ले, रा%य और देश में प्रयास होने आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत सरकार और ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किये जा रहे प्रयासों की विश्व में हर स्तर पर सराहना हो रही है। उनके निर्णयों-निष्कर्षों का सारी दुनिया के विकास में प्रयोग हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी के निष्कर्ष क्षेत्र, देश और विश्व के लिये उपयोगी होंगे।

केवल आधार कार्ड से मिलेगा कृषि पम्प कनेक्शन

भोपाल। पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने-अपने क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना (कृषि संकल्प) प्रारंभ की है। योजना में कृषि उपभोक्ताओं के अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में बदला जा रहा है। कृषकों के द्वारा आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नई प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटर आधारित है। इसमें कृषक को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड साथ लाना होगा। आवेदन, कृषक स्वयं अथवा किसी के भी द्वारा भरा जा सकता है। इसी प्रकार राशि कंपनी के किसी भी वितरण केन्द्र में जमा की जा सकती है। कृषक को अपने वितरण केन्द्र पर निर्भर रहने की बाध्यता नहीं रहेगी। राज्य शासन ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प योजना प्रारंभ की है, जिसमें कृषक उपभोक्ता अपना आवेदन नजदीकी वितरण केन्द्र, ऑनलाईन या प्रायवेट ऑनलाईन एजेंसी के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

शासन की इस योजना को कृषक उपभोक्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों से कहा है कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और मध्य प्रदेश को अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन से मुक्ति दिलवाने में योगदान करें।

गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश बनाने आगे आयें, सभी जिलों में बनेंगे युवा क्लब

भारत छोड़ो आंदोलन की 75वी वर्षगाँठ पर युवाओं से संवाद

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से आव्हान किया कि वे नये भारत का निर्माण करने के लिये नये मध्यप्रदेश का निर्माण करने आगे आयें। उन्होंने कहा कि यूथ फॉर न्यू मध्यप्रदेश की अवधारणा के अंतर्गत सभी जिलों में युवा क्लब बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लें। श्री चौहान यहां शौर्य स्मारक प्रांगण में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वी वर्षगाँठ पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को सीमाओं पर तैनात जाबांज जवानों से संवाद करने भेजने और देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिये शुरू की गई माँ तुझे प्रणाम योजना में अब अंडमान और निकोबार को भी शामिल किया जायेगा ताकि युवा जान सकें कि क्रांतिकारियों ने कितनी यातनायें सहीं।

श्री चौहान ने युवाओं से आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लेने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आतंकवाद, संप्रदायवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद मुक्त भारत का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने में मध्यप्रदेश के युवा भी भरपूर योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से संवाद करते हुये उन्हें विस्तार से बताया कि आजादी की लड़ाई की शुरूआत कैसे हुई और कैसे क्रांतिकारी एवं अहिंसात्मक आंदोलन साथ-साथ चले। उन्होंने कहा कि आजादी आसानी से नहीं मिली। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरूआत 1857 से हुई। क्रांतिकारियों ने मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च किया। श्री चौहान ने कहा कि अपनों की गद्दारी के कारण 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी लेकिन लड़ाई जारी रही। लाल, बाल, पाल की जोड़ी ने क्रांति में नई जान फूंकी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। एक तरफ क्रांतिकारियों का आंदोलन था दूसरी तरफ अहिंसावादी आंदोलन था। उन्होंने युवाओं को बताया कि कैसे क्रांतिकारियों ने यातनायें सहीं। कैसे चन्द्रशेखर, सुभाषचन्द्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिये काम किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन हर देशभक्त नागरिक का आंदोलन बन गया था। मध्यप्रदेश में भी कई क्रांतिकारियों ने कुरबानी दी। बैतूल में ग्यारह देशभक्त शहीद हुये, इंदौर में दस और जबलपुर में भी क्रांतिकारियों ने आजादी के लिये अपनी जान दी।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश युवाओं का प्रदेश है। युवाओं के लिये राज्य सरकार ने कई अनूठी योजनायें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी शिक्षा में धन की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रेक्टर योजना जैसी योजनायें गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं का आव्हान किया कि इन योजनाओं का लाभ उठाने आगे आयें। नौकरी मांगने वाले नही नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि वे युवाओं को आशाओं और आत्मविश्वास से भरा देखना चाहते हैं। वे प्रदेश के लिये सही दिशा में सोचें और अच्छा काम करें। श्री चौहान ने युवाओं को नया मध्यप्रदेश गढ़ने का संकल्प दिलाया और कहा कि आगामी 15 अगस्त को सभी युवा उत्साहपूर्वक मनायें।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत को आजादी दिलायी। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे आजादी को चिरस्थायी बनाने का संकल्प लें। उन्होने युवाओं को भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति से जोड़ने की पहल करने के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इससे पहले श्री चौहान ने भोपाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों श्री मानिक चंद चौबे, श्रीमती शर्मा, श्री जमीर खान, श्री मुख्तार खान, श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया।

श्री चौहान ने विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में दी गई प्रस्तुतियों के लिये एक-एक लाख रूपये की सम्मान निधि देने की घोषणा भी की। प्रारंभ में श्री चौहान ने शौर्य स्मारक में अमर शहीदों का स्मरण किया और श्रद्धासुमन अर्पित किये। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और प्रतीक स्वरूप आजादी की मशाल प्रज्जवलित की।

श्री सारंग ने छोला और ऐशबाग में पहुंचकर राखी बंधवाई

हजारों की संख्या में बहनों ने राखियाँ बाँधीं

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज छोला दशहरा मैदान और ऐशबाग स्टेडियम के सामने चाणक्यपुरी चौराहे के पास पहुँचकर बहनों से राखी बँधवाई। राज्य मंत्री श्री सारंग पिछले 8 वर्षों से लगातार विधानसभा क्षेत्र में पहुँचकर राखी महोत्सव में बहनों से राखी बँधवाते आ रहे हैं। इस क्रम में यह नवां वर्ष है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने राखी महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबँधन पर्व भाई और बहन के बीच का रिश्ता है। भाई और बहन परस्पर एक-दूसरे के प्रति सदभाव और प्यार का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले वर्षों से लगातार नरेला विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबँधन पर्व के अवसर पर राखी बँधवाने आते हैं। बहनें भी पूरी उत्सुकता के साथ रक्षाबँधन पर्व का इंतजार करती हैं और रक्षाबँधन महोत्सव में हजारों की संख्या में बहनें उनकी कलाई पर राखी भी बाँधती हैं। यह बहुत सुखद अवसर होता है। उन्हें इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। छोला दशहरा मैदान और ऐशबाग क्षेत्र में हजारों की संख्या में बहनों ने राखी बाँधी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने धर्मपत्नी श्रीमती रूमा सारंग के साथ सभी बहनों से राखी बँधवाई।

समय पर करें राजस्व प्रकरणों का निराकरण : मुख्य सचिव

राजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न

भोपाल। सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय पर करना सुनिश्चित करें। अपने राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण कर प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करें। आरसीएमएस पोर्टल पर सभी प्रकरण 10 दिन के अंदर दर्ज किये जाये ताकि प्रकरणों की मॉनीटरिंग बेहतर ढंग से की जा सके । यह निर्देश मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने सागर में राजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक दिए।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी सजग रहकर जिम्मेदारी से कार्य करें। रीडर या क्लर्क के भरोसे अपने कार्य न छोड़े। राजस्व प्रकरणों की सतत मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि दो माह बाद राजस्व संबंधी कार्यों की फिर से समीक्षा की जायेगी। इस दौरान कोई शिकायत मिली तो सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी नया प्रकरण आने पर उसे तत्काल आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज करायें। रिक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद शीघ्र भरें। उन्होंने हर गांव में बी-1 पढ़कर सुनाने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का शीघ्रता से शत प्रतिषत निराकरण करें। डायर्वसन, नजूल एवं अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत वसूली करें। शासकीय राजस्व बढ़ाने के लिए हरसंभव से प्रयास करें।

मुख्य सचिव ने प्रत्येक पटवारी के बस्तों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षकों के कार्यो की भी संपूर्ण जांच कर ली जाये ताकि प्रकरणों के निराकरण में प्रगति आ सके। उन्होंने डायर्वसन पंजी बनाने, नजूल का सर्वे कराने एवं नजूल पट्टों का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों को रिकार्ड रूम में रखने के पूर्व उनका पूरा रिकार्ड दुरूस्त कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि वर्षा के मौसम में भी सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण करें। वर्षा में ईटीएस मशीनों से सीमांकन का कार्य आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची से किसी का नाम काटने के बाद उसे राजस्व रिकार्ड से भी काट दिया जाये। राजस्व संबंधी कार्यो के लिए ग्राम सभाएं आयोजित करायें। उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रश्नों के मामले में राजस्व विभाग की स्थिति सुधारें।

बैठक में सीएम हेल्पलाईन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने क्षेत्र में जाकर सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण करने एवं लोक सेवा केन्द्रों की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देष दिए। उन्होंने आबादी घोषित करने एवं पट्टों के संबंध में अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में संभाग कमिश्नर डॉ. मनोहर अगनानी ने संभाग के राजस्व संबंधी कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संभाग में अधिकांश प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज है। शेष प्रकरण अगले 7 दिवस में दर्ज करा लिये जायेंगे। संभाग में 6524 में से 92 प्रतिशत सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। इसी तरह बंटवारा के 12134 प्रकरणों में से 60 प्रतिशत, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के 9656 प्रकरणों में से 79 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। डायवर्सन के 60 प्रतिषत आदेशों में वसूली की जा चुकी है। मुख्यमंत्री की 33 घोषणाओं में से 30 का निराकरण हो चुका है। शेष 3 शासन स्तर पर लंबित है। आरसीएमएस पोर्टल पर सागर संभाग 6वें स्थान पर है। बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री अरूण पाण्डेय, सचिव एवं आयुक्त भू-अभिलेख ने भी आवश्यक निर्देश दिए।

बाग प्रिंट ने अमेरिका वासियों का फिर मन मोहा भारत की ओर से मोहम्मद युसूफ खत्री शामिल हुए

भोपाल। विश्व में अपनी पहचान बना चुकी मध्यप्रदेश की बाग हस्तशिल्प कला ने एक बार फिर अमेरिका में लोगों का मन मोहा है। यह पहला मौका है कि भारत की ओर से धार जिले के बाग कस्बे की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला का अमेरिका में दूसरी बार प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में अमेरिका के सेन्टा फे शहर में हुए अंतर्राष्ट्रीय फोकआर्ट मार्केट में भारत की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद युसूफ खत्री ने परम्परा गत आदिवासी हस्त कला का परचम फहराया। इस प्रदर्शन-सह-बिक्री आयोजन में विश्व के 90 देशों ने भाग लिया।

फोक आर्ट मार्केट की निदेशक साचिको उमी ने बाग प्रिंट की सराहना करते हुए कहा कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कलाकारों को आगे मौके दिये जाने चाहिये। मोहम्मद युसूफ खत्री ने अमेरिका की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक एवं परम्परागत परिधान डिजाइन किये थे। इनकी प्रदर्शनी में काफी लोकप्रियता रही। तीन दिवसीय प्रदर्शनी में श्री युसूफ के सिल्क स्कार्फ, स्टोल, टेबल रनर, बेम्बू मेट की काफी माँग रही।

विभिन्न देशों में श्री युसूफ के बाग प्रिंट को मिली है सराहना

मोहम्मद युसूफ खत्री वर्ष 2009 में भी अमेरिका के फोट आर्ट मार्केट में अपनी हस्तकला का यादगार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बारर्सिलोना स्पेन में वर्ष 1991, हेनोवर जर्मनी के वर्ल्ड एक्सपो 2000, मार्टेनिक फ्रांस 2005, बारर्सिलोना स्पेन में वर्ल्ड एक्सपो 2005, बेहरीन में सुकल हिन्द फेस्टिवल 2006, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2006, इटली के मिलान में मेकेफेयर 2009, कोलम्बिया के बगोटो शहर में आर्टिजनों हैण्डीक्राफ्ट फेयर 2009, मिनाल इटली फेयर 2010, अर्जेंटीना के ब्यूनिसआयर्स में भारत महोत्सव 2011 सहित देश के कई नगरों में अपनी कला का जीवंत प्रदर्शन कर चुके हैं।

खरीफ की 109 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी

प्रदेश में 438.7 मि.मी. हुई है औसत बारिश

भोपाल प्रदेश में खरीफ सीजन में इस वर्ष अब तक 109 लाख 28हजार हेक्टेयर में बोनी की जा चुकी है। इस वर्ष 132 लाख 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सीजन में बोनी का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रदेश के किसानों ने इस वर्ष 16 लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बोनी की है जो निर्धारित कार्यक्रम से अधिक है। राज्य में इस वर्ष उड़द की बोनी का लक्ष्य 12 लाख हेक्टेयर तय किया गया था।

प्रदेश में किसानों ने 45 लाख 56हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी की है। खरीफ सीजन में करीब 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बोनी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राज्य में सोयाबीन की बुआई का उचित समय 15 जुलाई तक माना गया है। किसान-कल्याण विभाग ने किसानों को सोयाबीन के संबंध में सलाह दी है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की बुआई कर ली है, वे खेतों में जगह-जगह फन्सेदार खूटी गाड़ें, जिससे पक्षी उन पर बैठकर इल्लियों को नष्ट कर सकें। जिन खेतों में जल-भराव की स्थिति है, वहाँ किसान भाईयों को तुरंत जल-निकासी की व्यवस्था करनी चाहिये। किसानों को 20 दिन से अधिक उम्र की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने की सलाह दी गयी है। किसानों से कहा गया है कि वे फसल में कीट दिखाई देने पर अपने नजदीक के कृषि विस्तार अधिकारी से परामर्श कर उचित तरीके से कीट-नाशक का इंतजाम करें। प्रदेश में किसान अब मुख्य रूप से दालों अथवा ज्वार, मक्का और चारे वाली फसल आदि की विलंबित किस्म बो सकते हैं। प्रदेश में अब तक 438.7 मि.मी. औसत वर्षा हुई है, जबकि प्रदेश में इस अवधि में सामान्य औसत वर्षा 437.4 मि.मी. होती है।

राज्य में धान की 13 लाख 20 हजार हेक्टेयर में और मक्का की 12 लाख 58 हजार हेक्टेयर में बोनी की जा चुकी है। किसानों द्वारा 5 लाख 73 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बोनी की गयी है।

मूंग की समर्थन मूल्य पर हुई 2 लाख 17 हजार 167 मीट्रिक टन खरीदी

एक लाख से अधिक किसानों को किया गया भुगतान

भोपाल। प्रदेश में किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। समर्थन मूल्य पर 31 जुलाई तक मूंग की 2 लाख 17 हजार 167 मीट्रिक टन खरीदी की जा चुकी है। मूंग खरीदी के एवज में एक लाख 2 हजार 872 किसानों को 506 करोड़ 61 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। समर्थन मूल्य पर उड़द की 39 हजार 271 मीट्रिक टन खरीदी की गयी है। किसानों को खरीदी गयी उड़द के एवज में 26 करोड़ 51 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

किसानों को उनकी उपज का भुगतान नियत समय में करवाया गया है। कृषि उपज मण्डी परिसर में किसानों की सुविधा के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर से मुलाकात

मैट्रो रेल परियोजना की नयी नीति में ग्वालियर और जबलपुर को शामिल करने का आग्रह

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहरों में चल रही मैट्रो रेल परियोजना के बारे में चर्चा की। श्री चौहान ने बताया कि अभी प्रदेश के दो शहर इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य चल रहा है। श्री चौहान ने आग्रह किया कि प्रस्तावित नई नीति के अंतर्गत ग्वालियर और जबलपुर को भी मेट्रो रेल परियोजना में जोड़ा जाय। श्री चौहान ने बताया कि मेट्रो रेल भविष्य की आवश्यकता है। ग्वालियर और जबलपुर दोनों 20 लाख से %यादा आबादी वाले शहर हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ग्वालियर और जबलपुर शहर में मेट्रो की डी.पी.आर. तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

बैठक में ग्वालियर शहर में उत्पन्न पानी की समस्या पर भी चर्चा की गई। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए इसका शीघ्र निदान करने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि चम्बल नदी से पानी को अपलिफ्ट कर ग्वालियर के तिगरा बांध में डाला जाय जिससे कि ग्वालियर शहर की पानी की आवश्यकता पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस पर सहमति जताते हुए उपस्थित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मध्यप्रदेश की नगरी विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी मौजूद थीं।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये 415 काम्बेट टीम गठित

जल-जनित बीमारी होने पर कॉल-सेन्टर में तत्काल सूचना दें

भोपाल। जल जनित बीमारियाँ- डायरिया, आंत्रशोथ, हैजा और बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिये प्रदेश में जिला एवं विकासखंड स्तर पर 415 काम्बेट टीम का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्या मूलक गाँव और कस्बों को चिन्हित कर सतत निगरानी रखी जा रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रामक रोगों की दैनिक समीक्षा के दौरान दी गई। लोगों से कहा गया है कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जल-जनित बीमारी फैलने पर दूरभाष क्रमांक 0755- 4094192 एवं कॉल-सेन्टर 8989988712 पर तत्काल सूचना दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने बताया कि हर साल गर्मी की समाप्ति और वर्षा ऋतु के आरंभ पर पहले पानी की कमी फिर वर्षा के कारण पानी प्रदूषित होने पर जल-जनित बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। प्रदेश के प्रत्येक गाँव के आरोग्य केन्द्र तथा डिपो होल्डर के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउण्डर, जीवन रक्षक घोल, क्लोरीन, क्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल, मैट्रोनिडाजॉल आदि की गोलियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। सेक्टर प्रभारी, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और आशा के माध्यम से संक्रामक बीमारियों के तत्काल रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं। किसी गाँव में बीमारी प्रकरण होने पर आशा इसकी सूचना संबंधित विकासखंड चिकित्सा अधिकारी को देती है ताकि उसकी रोकथाम के तत्काल कदम उठाये जा सकें।

श्री सिंह ने दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिये ये सावधानी बरतने की अपील की है। खाने-पीने में हमेशा साफ- शुद्ध पानी का उपयोग करें। शौच से आने के बाद साफ पानी और साबुन से हाथ अच्छी तरह धोयें। ताजे बने भोजन और खाद्य वस्तुओं का सेवन करें। हमेशा भोजन व अन्य खाद्य सामग्री को ढंक कर रखें ताकि मक्खियों, धूल आदि से दूषित न हो। यदि पानी दूषित लगता हो तो उसे उबालकर साफ कपड़े से छान लें। क्लोरीन की गोली डालें, एक घंटे बाद उपयोग करें।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाईन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया और संक्रामक रोगों की दैनिक समीक्षा में बताया गया कि 1 जुलाई से 8 अगस्त तक स्वाईन फ्लू के 95 सेम्पल भेजे गये जिनमें 91 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को एनएचडीसी ने सौंपा 374 करोड़ 46 लाख 24 हजार रुपये का लाभांश चैक

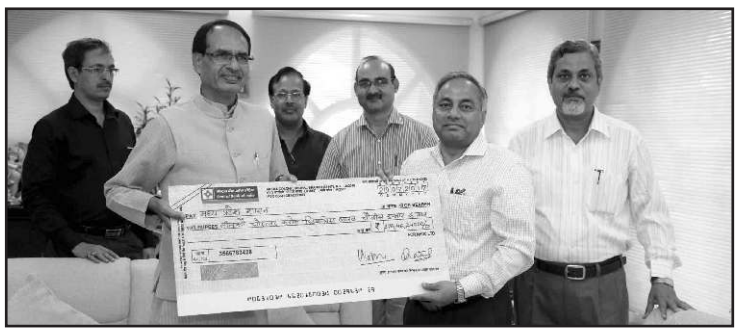

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एनएचडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एम.ए.जी अंसारी ने वर्ष 2016-17 का लाभांश चैक मुख्यमंत्री निवास में सौंपा।

उद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा रीवा में की योजनाओं की समीक्षा

भोपाल। वाणिज्य, उद्योग, रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना, गौ-अभ्यारण्य निर्माण, विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट आदि निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। श्री शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि योजनाबद्ध तरीके से तय मानदण्डों के अनुसार ही सीवरेज पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाये। पेयजल आपूर्ति के लिये जिन पानी की टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें पानी भरने और आपूर्ति का कार्य शीघ्र शुरू किया जाये। उन्होंने नागरिकों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवाने, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिये। उद्योग मंत्री ने बरसात में जल-भराव की स्थिति से निपटने की विस्तृत कार्य-योजना बनाने की आवश्यकता बताई।

श्री शुक्ल ने 45 एकड़ भूमि पर बनने वाले कचरे के एकत्रीकरण के कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि माह दिसम्बर के पूर्व बाउण्ड्री-वॉल निर्माण के साथ ही अन्य कार्य पूरे कर लिये जायें, ताकि अगले वर्ष जनवरी माह से कचरे का एकत्रीकरण प्रारंभ किया जा सकेगा। उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि निर्माण कार्य तीव्र गति से पूर्ण किया जाये।

समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी की अनियमितता की जाँच के लिये समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन ने वर्ष 2017-18में समर्थन मूल्य पर दलहन उपार्जन केन्द्र तेन्दूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर में अनियमितता की जाँच के लिये 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण के आयुक्त श्री विवेक पोरवाल, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक श्री मोहनलाल मीणा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के महाप्रबंधक श्री भगवान सिंह खेडेकर को मनोनीत किया गया है। समिति जाँच कर 15 दिवस में प्रतिवेदन कृषि उत्पादन आयुक्त को प्रस्तुत करेगी।

सरदार सरोवर विस्थापितों के लिये मध्यप्रदेश सरकार की एक और संवेदनशील पहल

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरदार सरोवर डूब प्रभावितों को पूर्व और वर्तमान में दी गई सुविधाएं तथा आर्थिक पैकेज

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

सरदार सरोवर डूब प्रभावित परिवारों को पूर्व में दिये गये लाभ :

- डूब प्रभावित परिवारों को पूर्व में उनकी अचल संपत्ति के मुआवजों के रूप में 526 करोड़ रुपये।
- प्रभावित पात्र परिवारों को पुनर्वास अनुदान मद में 38 करोड़ 83 लाख रुपये तथा रोजगार संपत्ति क्रय करने के मद में कुल 27 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान।
- प्रभावित परिवारों को पुनर्वास स्थलों पर 5400 वर्गफिट का भू-खण्ड नि:शुल्क। भू-खण्ड नहीं लेने वाले परिवार को इसके बदले 50 हजार रुपये।
- प्रभावित परिवारों को भूमि के बदले भूमि के रुपये 5 लाख 58 हजार के विशेष पैकेज के अंतर्गत् 188 करोड़ रुपये।

सरदार सरोवर डूब प्रभावितों को वर्तमान में दिये गये लाभ :

उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार-

- पूर्व का विशेष पैकेज नहीं लेने वाले 681 परिवारों को प्रति परिवार रुपये 60 लाख।
- पात्रता अनुसार अन्य 943 परिवारों को प्रति परिवार रुपये 15 लाख।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा घोषित :

- विशेष पुनर्वास पैकेज ले चुके परिवारों को भी प्रति परिवार रुपये 15 लाख।
- पुनर्वास स्थल पर मकान निर्माण तथा अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के लिये प्रति परिवार रुपये 5 लाख 80 हजार।
- जिन परिवारों की 25 प्रतिशत से कम भूमि डूब से प्रभावित है, उन्हें पूर्व में कोई पैकेज नहीं था, अब उन्हें डूब भूमि के समानुपात में रुपये 15 लाख।
- जिन परिवारों की 25 प्रतिशत से ऊपर भूमि पुनर्वास स्थल निर्माण के लिये ली गई थी, उन्हें पूर्व में कोई पैकेज नहीं था। अब इन्हें भी रुपये 15 लाख का पैकेज।
- किसानों को पाइपलाइन क्षति का मुआवजा।
- पुनर्वास स्थलों के सतत् विकास कार्यों के लिये रुपये 200 करोड़।
- पैकेज राशि से कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन करने पर रुपये 50 करोड़।
- महात्मा गांधी स्मारक निर्माण के लिये रुपये 5 करोड़।
- मंदिर/धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिये मूल मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज की पूर्ति के लिये रुपये 27 करोड़।
- पूर्व प्रावधान में भू-खण्ड के बदले रुपये 50 हजार लेकर, कहीं भी मकान निर्माण नहीं करने वाले परिवार को भी 180/150 वर्गफिट का भू-खण्ड नि:शुल्क।

सरदार सरोवर परियोजना के लाभ :

अंतर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य को विभिन्न लाभ मिलेंगे।

- परियोजना से बनने वाली बिजली का अधिकतम 57 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश को, 27 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र को और 16 प्रतिशत भाग गुजरात को मिलता है।
- बांध की वर्तमान 121.92 मीटर ऊंचाई से बन रही बिजली के 57 प्रतिशत भाग के रूप में मध्यप्रदेश को औसतन 1750 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है। गेट स्थापित होने के बाद जल भराव से 1300 मिलियन यूनिट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इस प्रकार इसके 57 प्रतिशत भाग के रूप में मध्यप्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 750 मिलियन यूनिट बिजली अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।
- सरदार सरोवर का जो क्षेत्र मध्यप्रदेश में है, उसमें मछली उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सकेगा। जलाशय/नदी से बड़ी संख्या में किसान उद्वहन कर सिंचाई का लाभ ले सकेंगे।
- परियोजना से गुजरात राज्य में लगभग 20 लाख और राजस्थान में लगभग 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई के साथ ही सैकड़ों नगरों, ग्रामों को पेयजल तथा औद्योगिक जल उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों के लिये घोषित उपरोक्त पैकेज रुपये 900 करोड़

विस्थापित परिवारों की सजग और संवेदनशील संरक्षक - मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2017

D-81701/17

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।